CEASI TIMES

21st July 2025

HINDI

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEFMI
Centre of Excellence for Farm Mechanization Skills in India

CEHSI
Centre of Excellence for Horticulture Skills in India

www.ceasi.in

हमारे बारे में

हम कौन हैं:

"सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)" एक स्वायत्त संस्था है, जो "एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)" के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoE-CRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्कफोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क का निर्माण।

हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशलयुक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- 15+ राज्य
- 15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया
- 20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया
- 5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया
- 3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया
- 30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया

आईसीएआर-डीडब्ल्यूआर ने तकनीक के व्यवसायीकरण के लिए विद्याश्री ट्रेडर्स से समझौता कि

आईसीएआर-निदेशालय खरपतवार अनुसंधान (आईसीएआर-डीडब्ल्यूआर), जबलपुर ने एक नवीन कृषि उपकरण 'एडजस्टेबल स्प्रे बूम होल्डिंग अटैचमेंट फॉर मल्टी-नोजल नैपसैक स्प्रेयर' के लाइसेंसिंग और व्यवसायीकरण के लिए विद्याश्री ट्रेडर्स, जबलपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह एमओयू डॉ. पी. के. सिंह, प्रमुख वैज्ञानिक एवं प्रभारी निदेशक, आईसीएआर-डीडब्ल्यूआर, और श्रीमती रश्मि जैन, प्रोप्राइटर, विद्याश्री ट्रेडर्स द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। यह उपकरण छिड़काव की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है, जो समान स्प्रे कवरेज, समायोज्य ऊंचाई और कम ऑपरेटर थकान प्रदान करता है। यह खेतों में अधिक प्रभावी और किफायती खरपतवार प्रबंधन में सहायक होने की उम्मीद है।

यह सहयोग स्थानीय निर्माण और वितरण के माध्यम से तकनीक की व्यापक उपलब्धता को आसान बनाने का प्रयास करता है। इस हस्ताक्षर समारोह में आईसीएआर-डीडब्ल्यूआर के वैज्ञानिक, पीएमई और आईटीएमयू प्रकोष्ठ के सदस्य, तथा विद्याश्री ट्रेडर्स के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

यह पहल कृषि अनुसंधान को जमीनी स्तर पर उपयोग से जोड़ने की एक व्यावहारिक कोशिश को दर्शाती है, जो खेती की पद्धतियों को बेहतर बनाने के लिए एक सरल और उपयोग

आंध्र प्रदेश में गांव स्तर पर कृषि यंत्रों का सर्वे शुर

आंध्र प्रदेश राज्यभर में गांव स्तर पर एक सर्वे करेगा ताकि कृषि यंत्रों की उपलब्धता और उपयोग का आकलन किया जा सके। यह सर्वे 31 अगस्त तक पूरा किया जाना है और इसे कृषि सहायक, रायतु सेवा केंद्रों (आरएसके) के माध्यम से करेंगे, ऐसी जानकारी कृषि निदेशक दिल्ली राव ने दी।

इस पहल का उद्देश्य किसानों, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठनों), प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) और निजी एजेंसियों के स्वामित्व वाले यंत्रों की डिजिटल सूची तैयार करना है। इसमें सब्सिडी के साथ या बिना खरीदी गई मशीनरी की जानकारी, स्वामित्व, स्थिति और संचालन की स्थिति भी दर्ज की जाएगी।

यह आंकड़े राज्य की कृषि सूचना प्रबंधन प्रणाली (APAIMS 2.0) पर अपलोड किए जाएंगे। इस प्रयास से मांग-आधारित बजट योजना में मदद मिलेगी, कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) से डेटा को जोड़ा जाएगा और बिना उपयोग वाले यंत्रों की पहचान कर बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

यह सर्वे सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन (SMAM) और पीएम-किसान जैसी योजनाओं का समर्थन करता है और साथ ही एआई-आधारित फसल सलाह, रीयल-टाइम सीएचसी बुकिंग और ड्रोन स्प्रे जैसी भविष्य की सेवाओं की योजना में भी मदद करेग

गोवा में खाजन खेती के पुनरुद्धार की योजना, यंत्रीकरण को मिलेगा समर्थ

गोवा सरकार ने खाजन भूमि पर खेती को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है, जिसके तहत बंधों की मरम्मत और यंत्रीकृत कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि अब तक खाजन क्षेत्रों में बंधों और संबंधित संरचनाओं की मरम्मत पर लगभग ₹48 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

सावंत ने बताया कि अब लगभग 40 लाख वर्ग मीटर भूमि पर यंत्रीकृत तरीकों से खेती की जा रही है। उन्होंने फ्र जॉर्ज क्वाड्रोज़ के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से कई अब विभिन्न कृषि कार्यों के लिए सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत हैं।

विधायकों ने बंधों की मरम्मत में देरी, निधियों की उपलब्धता और सब्सिडी के कार्यान्वयन को लेकर चिंता जताई। आल्दोना विधायक कार्लोस फरेरा ने समय रहते मृदा संरक्षण और त्वरित अनुमोदनों की आवश्यकता बताई। सियोलिम की विधायक डेलिलाह लोबो ने विशेष रूप से बाड़बंदी के लिए सब्सिडी समय पर देने की मांग की, जबकि फातोर्डा विधायक विजय सरदेसाई ने कृषि को इको-टूरिज्म से जोड़ने का सुझाव दिया।

विधानसभा ने संबंधित अनुदानों को ध्वनिमत से पारित किया, जिसमें कई सदस्यों ने 'अमृतकाल कृषि नीति' का समर्थन किया और किसानों के हित में इसके शीघ्र कार्यान्वयन की मांग की।

किसानों के लिए उर्वरक और कीटनाशकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कदम

किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई निगरानी व्यवस्थाएँ लागू की हैं। कीटनाशक अधिनियम और नियमों के तहत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 12,511 निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं जो निर्माण इकाइयों और बिक्री केंद्रों से नमूने लेकर गुणवत्ता की जांच करते हैं। वर्ष 2020–21 से 2024–25 के बीच लगभग 3.56 लाख नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 9,088 नमूने निम्न गुणवत्ता के पाए गए और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की गई। उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) 1985 के तहत उर्वरकों की गुणवत्ता को नियंत्रित किया जाता है। इसमें रासायनिक, जैविक और जैव-उर्वरकों के मानक तय किए गए हैं। निर्धारित मानक से कम गुणवत्ता वाले उर्वरकों की बिक्री पर रोक है और उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जा सकता है, साथ ही कानूनी दंड भी हो सकता है।

किसानों को रसायनों का सीमित और सुरक्षित उपयोग करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। यंत्रों, कस्टम हायरिंग सेंटर और ड्रोन जैसी सुविधाओं के लिए SMAM जैसी योजनाओं से सहायता मिलती है। इसके अलावा, फसल अवशेष प्रबंधन, प्रति बूंद अधिक फसल और वर्षा आधारित खेती जैसे कार्यक्रम छोटे और सीमांत किसानों के लिए टिकाऊ और कुशल खेती को बढ़ावा दे रहे हैं।

भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुष्प उत्पादक राज्य बना मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा फूल उत्पादक राज्य बन गया है, जहाँ पिछले वर्ष 5,12,914 टन फूलों का उत्पादन हुआ। राज्य में फूलों का व्यवसाय तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। वर्तमान में राज्य में 42,978 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती की जा रही है। प्रमुख फूलों में गेंदा (24,214 हेक्टेयर), गुलाब (4,502 हेक्टेयर), सेवती, ग्लैडियोलस और रजनीगंधा शामिल हैं। औसतन प्रति हेक्टेयर उत्पादन 15.01 टन है।

फूलों की मांग देश-विदेश में लगातार बढ़ रही है। विशेष रूप से गुना जिले के गुलाब अब जयपुर, दिल्ली, मुंबई के साथ-साथ पेरिस और लंदन तक पहुँच रहे हैं। छोटे किसान परंपरागत फसलों के बजाय अब फूलों की खेती की ओर बढ़ रहे हैं और बेहतर आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2024–25 में फूलों की खेती में 5,329 हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। ग्वालियर में ₹13 करोड़ की लागत से हाई-टेक नर्सरी सहित तकनीकी जानकारी और आधारभूत सुविधाएं किसानों को प्रदान की जा रही हैं। पिछले चार वर्षों में फूलों के उत्पादन में 86,294 टन की बढ़ोतरी हुई है।

गुजरात में बागवानी क्षेत्र का 37% हिस्सा आम की खेती में

राष्ट्रीय आम दिवस के अवसर पर गुजरात सरकार ने बताया कि राज्य की कुल 4.71 लाख हेक्टेयर बागवानी फसलों में से 1.77 लाख हेक्टेयर (लगभग 37%) क्षेत्रफल में केवल आम की खेती होती है। वर्ष 2024–25 में गुजरात से 856 मीट्रिक टन से अधिक आम का निर्यात किया गया, जो राज्य की आम उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। गुजरात की अनुकूल जलवायु और मिट्टी के कारण केसर, अल्फांसो, राजापुरी, तोतापुरी और सोनपरी जैसी कई किस्मों की सफलतापूर्वक खेती की जाती है।

आम की खेती मुख्य रूप से वलसाड (38,000 हेक्टेयर), नवसारी (34,800 हेक्टेयर), गिर सोमनाथ (18,400 हेक्टेयर), कच्छ (12,000 हेक्टेयर) और सूरत (10,200 हेक्टेयर) जिलों में होती है। इस वर्ष गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग सुविधा के माध्यम से 224 मीट्रिक टन केसर आम का विकिरण करके निर्यात किया गया। यह गुजरात की पहली और भारत की चौथी एपीएचआईएस (USDA) प्रमाणित इकाई है, जो राज्य के बागवानी ढांचे की प्रगति को दर्शाती है।

बागवानी को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार देगी 50% फेंसिंग सब्सिडी

a Chief Minister, Sh.Nayab Singh Saini, who is also the Chairman of the
tee of Haryana International Horticultural Marketing Corporation Limited p
e 5th Steering Committee meeting at Chandigarh on July 26, 2025. Agricult
's Welfare Minister, Sh.Shyam Singh Rana is also seen in the picture.

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई पहल के तहत बागवानी फसलों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग पर 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है। यह योजना "समेकित बागवानी विकास मिशन योजना" के अंतर्गत चलाई जाएगी और "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर लागू की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य किसानों की लागत को कम करते हुए फसलों को आवारा पशुओं और अन्य बाहरी नुकसानों से सुरक्षित रखना है।

सरकार का उद्देश्य बागवानी किसानों की आय बढ़ाना और खेत स्तर पर सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। इस योजना से किसानों पर वित्तीय बोझ कम होगा और बेहतर अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल राज्य में बागवानी क्षेत्र के विकास को गति देने, कृषि अवसंरचना को मजबूत करने और सतत खेती को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

गन्नौर अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी के संचालन को मिलेगी गति

गन्नौर, सोनीपत में विकसित की जा रही अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी हरियाणा की प्रमुख कृषि अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है। 544 एकड़ में फैली इस परियोजना में 350 एकड़ में 17 आधुनिक शेड, 5,500 ट्रकों और 15,000 कारों की पार्किंग की सुविधा तथा वर्टिकल मार्केटिंग की व्यवस्था प्रस्तावित है। ₹2,595 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना की निविदा प्रक्रिया को तकनीकी समिति द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है। संचालन 'बिजनेस ऑपरेशन प्लान' के तहत किया जाएगा, जिसमें केवल वे निवेशक पात्र होंगे जिनके पास न्यूनतम 100 एकड़ बागवानी का अनुभव और ₹100 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर है।

परियोजना के संचालन में तेजी लाने हेतु एक विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो राज्य, केंद्र व विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा। यह मंडी दिल्ली की आजादपुर मंडी के व्यापारियों और हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए लाभकारी होगी, क्योंकि यह सुदृढ़ सड़क नेटवर्क से जुड़ी है। साथ ही, इस परियोजना को वैश्विक प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए एपीडा से तकनीकी मार्गदर्शन लेने की भी सिफारिश की गई है।

सरकार ने सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए पंचायती स्तर पर नई PACS, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की योजना शुरू की

सरकार ने देशभर में सहकारी आंदोलन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने के उद्देश्य से आगामी पांच वर्षों में 2 लाख बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख समितियों (M-PACS) के साथ-साथ डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की योजना शुरू की है। यह योजना का उद्देश्य डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (DIDF), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) जैसी विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के समन्वय से इसे लागू करना है। इस पहल में नाबार्ड (NABARD), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) और राज्य सरकारों का सहयोग लिया जा रहा है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, 30 जून 2025 तक देशभर में कुल 22,606 नई PACS, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां पंजीकृत की जा चुकी हैं। इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु 19 सितंबर 2024 को एक मानक संचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) जारी की गई, जिसमें लक्ष्य, समयसीमा और सभी संबंधित हितधारकों की भूमिकाएं स्पष्ट की गई हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 4,188 PACS, 9,149 डेयरी, और 200 मत्स्य सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जून 2025 तक राज्य में 891 डेयरी सहकारी समितियां (जिसमें से 5 कृष्णा जिले में हैं) और 2 मत्स्य सहकारी समितियां पहले ही पंजीकृत की जा चुकी हैं।

लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यशाला: देशी नस्लों के विकास और पशुधन उत्पादकता पर जोर

लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी कन्वेंशन सेंटर में "भारत में नस्ल विकास" विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में देशभर से 700 से अधिक पशुपालक, पशु चिकित्सक, विशेषज्ञ और नीति निर्माता शामिल हुए, जिन्होंने देशी पशु नस्लों के संरक्षण, आनुवंशिक सुधार और सतत पशुधन विकास पर विचार साझा किए।

कार्यशाला के दौरान ब्रिडर्स एसोसिएशन की स्थापना के लिए रूपरेखा और गोरखपुर में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया। साथ ही, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के तहत अमेठी, बरेली और मथुरा में तीन नई परियोजनाओं का लोकार्पण भी हुआ।

प्रमुख तकनीकों जैसे इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) और सेक्स सॉर्टेड सीमेन (SSS) पर विशेष जोर दिया गया, ताकि नस्ल की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। मुंह एवं खुर रोग (FMD) के उन्मूलन, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों पर भी चर्चा हुई।

दो तकनीकी सत्रों में नस्ल चयन, प्रदर्शन मूल्यांकन, दूध प्रसंस्करण, और मांस उत्पादन पर नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया गया। कार्यशाला को समावेशी और सतत पशुधन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

गडवासु ने भैंस पालन के भविष्य के लिए तैयार किया रोडमैप

गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशालय द्वारा 'भविष्य के लिए भैंस पालन: नीति, व्यवहार और संभावनाएं' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया और पंजाब सहित देश में टिकाऊ भैंस पालन को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा की।

कुलपति डॉ. जेपीएस गिल ने तरनतारन में भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की घोषणा की और उत्पादन सुधार के लिए रोडमैप साझा किया, जिसमें समय से पहले बियाई और मोज़ेरेला चीज़ व पारंपरिक मिठाइयों जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के विकास पर जोर दिया गया।

विशेषज्ञों ने उच्च बछड़ा मृत्यु दर, कमजोर प्रजनन नीति, तथा पोषण और दुग्ध तकनीक में कमियों जैसे मुद्दों को उठाया। प्रस्तावित समाधानों में भैंस ब्रोइलर मिशन, भैंस दूध का पृथक संग्रह, और कम लागत वाली शुद्धता जांच तकनीक शामिल थीं। संगोष्ठी में भैंसों के कम जल उपभोग और जलवायु अनुकूलता को भी रेखांकित किया गया।

दो तकनीकी सत्रों में प्रजनन, स्वास्थ्य, दुग्ध प्रसंस्करण और मांस उत्पादन के अवसरों पर चर्चा हुई। ओपन हाउस चर्चा में प्रगतिशील किसानों और अन्य हितधारकों ने भी अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। यह संगोष्ठी पंजाब में पशुधन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई।

16 राज्यों में वर्चुअल अभियान से जुड़े 2 लाख से अधिक पशुपालक किसान, डेयरी और पशुधन क्षेत्र में मिला नया मार्गदर्शन

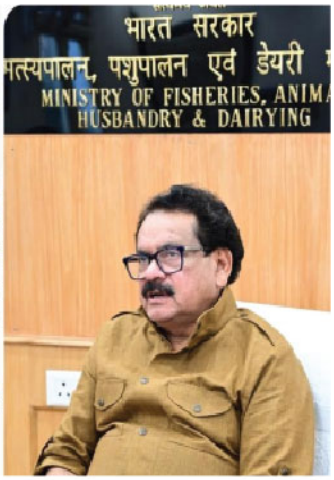

देशभर के 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 2 लाख से अधिक पशुपालक किसानों ने एक राष्ट्रीय वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया, जिसका उद्देश्य आधुनिक पशुपालन तकनीकों को बढ़ावा देना और किसानों को सरकारी योजनाओं एवं विशेषज्ञों से जोड़ना था। यह कार्यक्रम 4,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) के माध्यम से आयोजित किया गया।

इस पहल में बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम, जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों के किसान शामिल हुए। कार्यक्रम में कृत्रिम गर्भाधान, जीनोमिक चयन, बायो-सिक्योरिटी, और IVF व सेक्स सॉर्टेड सीमेन जैसी उन्नत तकनीकों पर जानकारी दी गई।

किसानों को पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी योजनाओं का लाभ लेने और FMD-मुक्त भारत अभियान से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके अंतर्गत अब तक 100 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।

अधिकारियों ने नस्ल सुधार, रोग नियंत्रण, पशुधन सहकारी समितियों के औपचारिकरण और ग्रामीण आय वृद्धि में पशुपालन क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित किया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ सत्रों और जानकारीपूर्ण वीडियो के माध्यम से किसानों को व्यावहारिक जानकारी और योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया।

डिजिटल कृषि क्रांति: e-NAM से जुड़े 1.79 करोड़ किसान, ₹4.39 लाख करोड़ का व्यापार

सरकार की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) योजना ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 30 जून 2025 तक 1.79 करोड़ किसान, 2.67 लाख व्यापारी, और 4,518 किसान उत्पादक संगठन (FPOs) इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो चुके हैं। अब तक 1,522 मंडियों को e-NAM से जोड़ा जा चुका है, जिसके माध्यम से कुल ₹4.39 लाख करोड़ का व्यापार संपन्न हुआ है।

e-NAM किसानों को बिचौलियों के बिना सीधे खरीदारों से जुड़ने का अवसर देता है, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित होती है। यह प्लेटफॉर्म रीयल-टाइम मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता ग्रेडिंग, ऑनलाइन बोली और ई-भुगतान जैसी सुविधाएं प्रदान करता है, जो पारदर्शिता और समय पर भुगतान को बढ़ावा देती हैं।

राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रस्तावों के आधार पर मंडियों को इस प्लेटफॉर्म में जोड़ा जाता है, जिससे देशव्यापी डिजिटल व्यापार नेटवर्क का निर्माण हो रहा है। समान गुणवत्ता मानक, समरूप व्यापार प्रथाएं और सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देकर e-NAM किसानों की आय, बाजार पहुंच और औपचारिक कृषि व्यापार में भागीदारी को लगातार सशक्त कर रहा है।

संसदीय समिति ने जैविक फसलों के लिए MSP, इनपुट और बाज़ार पहुंच बढ़ाने की सिफारिश की

एक संसदीय अनुमान समिति ने टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से चुनिंदा जैविक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) शुरू करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में जैविक उत्पादों को जो 20–30% अधिक दाम मिलते हैं, उसे एक संस्थागत MSP प्रणाली के तहत औपचारिक रूप देना चाहिए।

समिति ने जैविक खेती में प्रमुख चुनौतियों—जैसे अधिक श्रम लागत, सीमित बाजार पहुंच, और जैविक उर्वरकों की कमी—को रेखांकित किया। समिति ने कृषि मंत्रालय से आग्रह किया कि वह MOVCDNER जैसी योजनाओं के तहत जैविक इनपुट, प्रमाणन और आधारभूत ढांचे के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाए और कठिन इलाकों में लॉजिस्टिक सपोर्ट को बेहतर बनाए।

समिति ने जैविक उत्पादों के लिए शहरों में विशेष रिटेल आउटलेट खोलने जैसी बाज़ार कड़ी मजबूत करने की मांग की।

रिपोर्ट में NICRA परियोजना में मंत्रालय के कार्यों की सराहना की गई और मौसम व कीटों की पूर्व चेतावनी के लिए AI जैसी डिजिटल तकनीकों को बढ़ाने की सिफारिश की गई। साथ ही, तकनीकी संस्थानों के साथ साझेदारी कर इन टूल्स को किसानों तक पहुंचाने का सुझाव दिया गया।

इसके अलावा, कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) की नियमित रैंकिंग फिर से शुरू करने की सिफारिश की गई ताकि पारदर्शिता बनी रहे और प्रदर्शन में सुधार ह

भारत–यूके व्यापार समझौते से भारतीय किसानों को मिलेंगे नए अवस

हाल ही में हस्ताक्षरित भारत–यूके मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) से भारतीय किसानों को यूके के बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत 95% से अधिक भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद यूके में शून्य शुल्क पर निर्यात किए जा सकेंगे, जिससे अनाज, मसाले, समुद्री उत्पाद, फल और अचार जैसे कई उत्पादों को नए अवसर मिलेंगे।

इस कदम से व्यापार लागत कम होने और भारतीय कृषि निर्यात की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने की संभावना है। अधिकारियों का अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में यूके को कृषि निर्यात में 20% तक की वृद्धि हो सकती है। झींगा और टूना जैसे समुद्री उत्पादों को शुल्क समाप्त होने से विशेष लाभ होगा।

यह समझौता विविधीकरण को भी बढ़ावा देता है, जिससे मिलेट्स और जैविक उत्पाद जैसे नए आइटम अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच सकते हैं। साथ ही, घरेलू रूप से महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे डेयरी और खाद्य तेलों को संरक्षण भी प्रदान किया गया है।

कुल मिलाकर, यह समझौता किसानों और कृषि व्यवसायों के लिए निर्यात के अवसर बढ़ाएगा और कृषि क्षेत्र में टिकाऊ विकास को समर्थन देगा।

अरुणाचल में ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ₹28.17 करोड़ के कृषि ऋण वितरित

अरुणाचल प्रदेश में ग्रामीण आजीविका और कृषि विकास को सशक्त करने के उद्देश्य से दोइमुख में आयोजित मानसून क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान ₹28.17 करोड़ के कृषि ऋण 282 लाभार्थियों को वितरित किए गए। यह कार्यक्रम भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों के किसानों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और युवा उद्यमियों को 50 ऋण स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए। यह पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और सतत कृषि आधारित जीवनयापन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है।

कार्यक्रम को ग्रामीण उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), पीएमएफएमई और एफपीओ जैसी केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं का प्रभावी उपयोग कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। ऋण वितरण के पश्चात कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और ग्रामीण विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई।

ईस्कॉर्ट्सकुबोटा के सहयोग से सीईएफएमआई ने कुरुक्षेत्र में तीन दिवसीय एफपीओ प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया

सेंटर ऑफ फार्म मेक्नाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI) ने ईस्कॉर्ट्सकुबोटा लिमिटेड के सहयोग से 21 से 23 जुलाई 2025 तक कुरुक्षेत्र में तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के बोर्ड सदस्यों और सीईओ के लिए तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर यंत्रीकृत खेती को बढ़ावा देने के लिए नेतृत्व और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना था।

प्रशिक्षण के पहले दिन एफपीओ के लिए बेहतर संचालन मॉडल, बोर्ड की जिम्मेदारियाँ, संगठनात्मक संरचना और पारदर्शी निर्णय-निर्माण प्रक्रिया पर चर्चा की गई। दूसरे दिन प्रतिभागियों ने ट्रैक्टर, उसके अटैचमेंट और अन्य उन्नत कृषि यंत्रों के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया और संचालन तकनीक, सुरक्षा उपायों व नियमित रखरखाव के बारे में सीखा। अंतिम दिन एग्रीबिजनेस फाइनेंसिंग पर फोकस रहा, जिसमें क्रेडिट मूल्यांकन, कार्यशील पूंजी प्रबंधन और बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से जुड़ने की रणनीतियाँ शामिल थीं।

यह कार्यक्रम विशेषज्ञों द्वारा संचालित कक्षा सत्रों, जीवंत प्रदर्शन और आपसी चर्चा के माध्यम से आयोजित किया गया, जिससे प्रतिभागियों को नई तकनीकें सीखने, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल कृषि व्यवसाय को अपनाने में मदद मिली। प्रशिक्षण पूरा करने वाले सभी एफपीओ को प्रमाण पत्र दिए गए, जो उनके यंत्रीकरण और सतत विकास की दिशा में बढ़े कदम को दर्शाते हैं।

बाराबंकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया द्वारा तीन दिवसीय डेयरी फार्मर उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया ने स्किल ग्रीन ग्लोबल के सहयोग से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 15 से 17 जुलाई 2025 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह पहल ग्रामीण युवाओं और किसानों को डेयरी फार्मर उद्यमिता मॉडल के तहत सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई थी।

इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को वैज्ञानिक डेयरी पालन के तरीकों से अवगत कराना, डेयरी कार्यों में मशीनीकरण को बढ़ावा देना और उन्हें स्थायी आजीविका के लिए उद्यमिता की क्षमताएँ विकसित करना था।

कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को पशुपालन, चारा उत्पादन, स्वच्छता, वित्तीय योजना और डेयरी में उपयोग होने वाले आधुनिक मशीनी उपकरणों के प्रयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

यह कार्यक्रम पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकों के संयोजन से डेयरी क्षेत्र की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण उद्यमिता तथा समावेशी विकास को गति देग

सीईएएसआई और एएससीआई के सहयोग से एग्रीकल्चर मशीनरी डिमोंस्ट्रेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयो

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (सीईएएसआई) द्वारा एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) के सहयोग से एग्रीकल्चर मशीनरी डिमोंस्ट्रेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों से 250 बेनिफिशियरीज को एडवांस्ड फार्म मशीनरी के ऑपरेशन, मेंटेनेंस और डिमोंस्ट्रेशन में हैंड्स□ऑन स्किल्स प्रदान करना है।

यह प्रोग्राम खासकर रूरल यूथ, फार्म सर्विस प्रोवाइडर्स और एग्री□एंटरप्रेन्योरस के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे मॉडर्न, मेकैनिकाइज्ड और क्लाइमेट□स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकें। ट्रेनिंग में सीड ड्रिल, हार्वेस्टर, पावर वीडर और अन्य एडवांस्ड इक्विपमेंट्स का प्रैक्टिकल यूज सिखाया जाएगा, साथ ही सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ट्रबलशूटिंग और बेसिक रिपेयर्स की जानकारियाँ भी दी जाएँगी।

यह इनिशिएटिव स्किल गैप को ब्रिज करता है, जिससे फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मैनुअल ड्रेजरी कम होगी और टेक्नोलॉजी□ड्रिवन सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा मिले

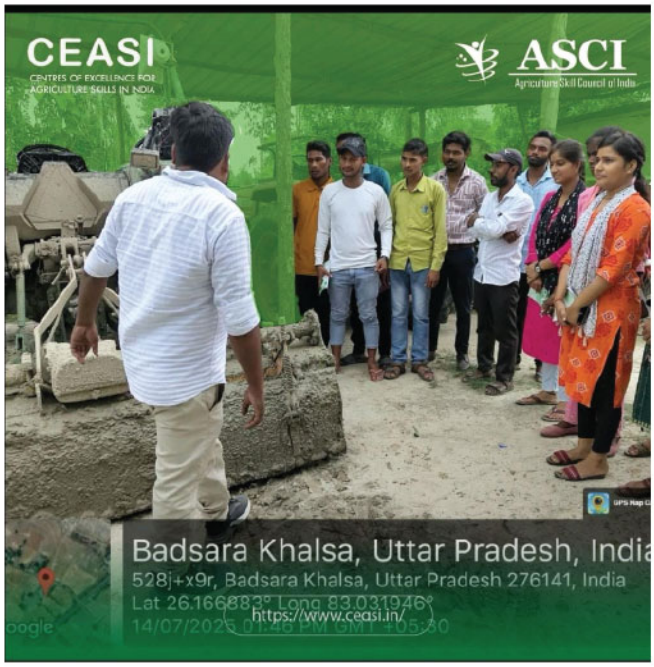

"अयोध्या में सतत गन्ना खेती को सशक्त बना रहा है 'सश्वत मिठास' अभियान"

'सश्वत मिठास' पहल के तहत, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया ने UPL SAS लिमिटेड के सहयोग से अयोध्या क्षेत्र में सतत (सस्टेनेबल) गन्ना खेती को बढ़ावा देना शुरू किया है। अब तक 431 किसानों का सर्वेक्षण किया जा चुका है—जिसमें 56 असंगठित और 3 संगठित किसान समूह शामिल हैं—ताकि वर्तमान खेती के तरीकों को समझा जा सके और सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जा सके।

सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारियों के आधार पर, गांव स्तर पर प्रदर्शन प्लॉट तैयार किए गए हैं, जहां जल प्रबंधन, मिट्टी की सेहत और जैविक इनपुट के उपयोग जैसी सर्वोत्तम खेती तकनीकों को प्रदर्शित किया जा रहा है।

समुदाय की भागीदारी और आपसी सीख को बढ़ावा देने के लिए, अब तक 50 किसान बैठकें, 8 फील्ड डे और 55 स्थानीय रिटेलर्स के साथ संवाद किए गए हैं। इन आयोजनों के दौरान किसान विशेषज्ञों से अपने सवालों पर चर्चा करते हैं और जलवायु अनुकूल तकनीकों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। फील्ड रिसर्च, प्रत्यक्ष प्रदर्शन और हितधारकों की भागीदारी के ज़रिए, यह पहल किसानों को पर्यावरण-अनुकूल और संसाधन-संरक्षण वाले तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे उपज में वृद्धि, पारिस्थितिकी का संरक्षण और जलवायु-स्मार्ट खेती को बढ़ावा मिल रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य न केवल गन्ने की उत्पादकता बढ़ाना है, बल्कि अयोध्या क्षेत्र में दीर्घकालिक कृषि स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन के लिए एक मॉडल खड़ा करना भी है।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI), जो **सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया** (CEASI) के अंतर्गत कार्य करता है, **5 अगस्त 2025 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, न्यू दिल्ली** में स्मार्ट पोस्ट-हार्वेस्ट स्ट्रैटेजीज़: वैल्यू एन्हांसमेंट, लॉस रिडक्शन एंड सप्लाई चेन एफिशिएंसी विषय पर एक राउंडटेबल का आयोजन कर रहा है। यह कार्यक्रम एग्रीकल्चर और स्किलिंग इकोसिस्टम से जुड़े प्रमुख स्टेकहोल्डर्स को एक मंच पर लाएगा, जहाँ हॉर्टिकल्चर सेक्टर में पोस्ट-हार्वेस्ट वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए इनोवेटिव और स्केलेबल अप्रोच पर चर्चा की जाएगी। यह राउंडटेबल सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

(CEASI), Unit No. 101, First Floor, Greenwoods Plaza, Block 'B' Greenwoods City, Sector-45, Gurugram, Haryana-122009

+91 74287 06078

info@cedsi.in

www.ceasi.in

@ceasi_india